भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 109
दिनांक 09 **फरवरी**, 2023

ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत

†*109. **श्री डी.एम.कथीर आनन्द**:
श्री अनुराग शर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए) का यह पूर्वानुमान है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 2023 में औसतन 95.33 अमेरिकी डॉलर/प्रति बैरल होंगी तथा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) ने 2023 में इनके औसतन 87.33 अमेरिकी डॉलर/प्रति बैरल होने का अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ब्रेंट क्रूड ऑयल और डब्ल्यूटीआई स्रोतों के लिए भारत की आयात संबंधी योजनाएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में पेट्रोल/डीजल/एलपीजी/सीएनजी/एलएनजी की कीमतों को कम करने के लिए कोई प्रयास किये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अत्यधिक आयात से संबंधित बाध्यताओं के कारण होने वाले भारी बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले नवोन्मेषी उपाय क्या हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(**श्री हरदीप सिंह पुरी**)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत' के संबंध में संसद सदस्य श्री डी.एम.कथीर आनन्द और श्री अनुराग शर्मा द्वारा दिनांक 09.02.2023 **को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं**. 109 **के भाग** (**क**) **से** (**ग**) **के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल का मूल्य मांग आपूर्ति परिदृश्य, भू-राजनैतिक मुद्दों तथा विभिन्न अन्य बाजार दशाओं पर आधारित है। कच्चे तेल के मूल्यों के बारे में, विशेषकर से चल रही अस्थिरता को देखते हुए बिल्कुल सही भविष्यवाणी करना मुश्किल कार्य है। भारत अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांशत: कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण तथा वार्षिक आवधिक संविदाओं और साथ ही अल्पकालिक हाजिर संविदाओं के माध्यम से कच्चे तेल के विभिन्न आपूर्ति स्रोतों के मूल्यांकन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं को वार्षिक आधार पर अंतिम रूप देती हैं। ओएमसीज तथा स्टैंडएलोन रिफाइनरियों द्वारा आवधिक और हाजिर संविदाओं के माध्यम से कच्चे तेल की इस अधिप्राप्ति के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कच्चे तेल की विभिन्न अनुकूल श्रेणियों (ब्रैंट/डब्ल्यूटीआई के लिए बैंचमार्क किए गए कच्चे तेल सहित) के लिए संविदा कर लिया गया है।

(ख) देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्यों से जुड़े हुए हैं। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित हैं। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। तथापि, संबंधित अंतरराष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने दिनांक 06 अप्रैल, 2022 से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को बढ़ाया नहीं है।

कच्चे तेल के मूल्यों में अत्यधिक अस्थिरता और बढ़े हुए मूल्यों के कारण अधिकांश विकसित देश उच्च पेट्रोल और डीजल मूल्यों के चपेट में हैं। उदाहरण के लिए यूएस में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में दिसंबर, 2021 से दिसंबर, 2022 की अवधि में क्रमशः 6% और 42% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत (दिल्ली) में इसी अवधि के दौरान पेट्रोल के मूल्य में 7% की कमी हुई और डीजल के मूल्य में केवल 3% की वृद्धि हुई है।

केन्द्र सरकार ने दो बार नवंबर,2021 और मई,2022 में पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कुल 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी की है। मई,2022 में उत्पाद शुल्क में कमी का लाभ पूरी तरह से उपभोक्ताओं को दे दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप खुदरा बिक्री मूल्यों में कमी आई। इस उपाय का उद्देश्य अर्थ यवस्था को गति प्रदान करना तथा खपत बढ़ाना और मुद्रास्फीति को कम बनाए रखना था ताकि गरीबों और मध्यम वर्ग की मदद की जा सके। बाद में, अनेक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट दरें कम कर दी हैं।

औसत सऊदी सीपी मूल्य, जिन पर घरेलू एलपीजी के मूल्य आधारित होते हैं, वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 454 यूएस डॉलर/एमटी से बढ़कर 693 यूएस डॉलर/एमटी हो गए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान फरवरी, 2023 तक औसत सऊदी सीपी और बढ़कर 710 यूएस डॉलर/एमटी हो गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 के अंत तक 14.2 किलो ाम के सिलेंडर (दिल्ली) का आरएसपी क्रमशः 805.50 रुपए/सिलेंडर, 819 रुपए/सिलेंडर, 949.50 रुपए/सिलेंडर तथा दिनाँक 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार 1053 रुपए/सिलेंडर रहा है।

सरकार घरेलू एलपीजी के उभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती बढ़ाती रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंम नियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर काफी हानि हुई है। इस हानि की भरपाई करने के लिए सरकार ने हाल ही में ओएमसीज को 22,000 करोड़ रुपए के एकबारगी मुआवजे का भुगतान किया है।

किसी भी स्थल पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के मूल्यों का निर्धारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंमनी द्वारा अधिप्राप्त गैस की लागत, रा य करों, प्रशुल्क तथा अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) का आयात विभिन्न प्राकृतिक गैस उपभोक्ताओं, विपणनकर्ताओं आदि द्वारा दीर्घकालिक संविदाओं के आधार पर और हाजिर बाजारों में किया जाता है। एलएनजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रेत्ता और विक्रेत्ता के बीच वाणि ियक सहमति से तय होते हैं। तथापि, भारत में सीएनजी मूल्यों पर अंतरराष्ट्रीय गैस मूल्यों में होने वाली वृद्धि के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2013-14 में सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) को घरेलू एपीएम गैस आवंटन में लगभग 250% की वृद्धि करने, सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए विद्युत तथा अन्य गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से घरेलू गैस का विपथन करने और घरेलू गैस के आवंटन के लिए सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) क्षेत्र को पहली प्राथमिकता के रूप में घोषित करने सहित अनेक कदम उठाए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार (जेकेएम) में गैस के मूल्यों में जनवरी, 2021 तथा नवंबर, 2022 के बीच 327% की वृद्धि हुई है जबकि भारत में इसी अवधि के दौरान सीएनजी के मूल्य (दिल्ली) में केवल 84% की वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार ने आयातित कच्चे तेल पर देश की तेल निर्भरता में कमी करने के उद्देश्य से पंच उद्देश्यीय कार्यनीति अपनाई है जिसमें तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना, मांग प्रतिस्थापन पर जोर देना, जैव ईंधनों तथा अन्य वैकल्पिक ईंधनों/नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार आदि शामिल हैं।

घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने तथा आयात में कमी करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, तेल और गैस के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति में सुधार 2019, प्राकृतिक गैस विपणन सुधार 2020, तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना, मौजूदा परिपक्व क्षेत्रों का पुनर्विकास और नए/सीमांत क्षेत्रों का विकास, रुग्ण कूपों का पुनरु ार, उन्नत तेल निकासी (आईओआर) और वर्धित तेल निकासी (ईओआर) तकनीक के कार्यान्वयन के जरिए निकासी को आदि शामिल हैं। सरकार ने राष्ट्रीय तेल कंम नियों को कार्यात्मक आजादी भी प्रदान की है और इलैक्ट्रोनिक एकल पटल व्यवस्था के जरिए अनुमोदन प्रक्रिया को व्यवस्थित करके निजी क्षेत्र की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

****